

तापमान : अधिकतम 31.5°C, न्यूनतम 16.2°C

बस्सी में एमएल गृह उद्योग पर कार्रवाई: स्टार्च, पानी व रंग से साँस बनाने का अंदेशा, 6 हजार बोतलें सीज, भाव 20-22 रुपए लीटर

बना रहे थे वेजिटेबल साँस मगर सब्जी का निशान तक नहीं



पत्रिका
सेहत के
सौदागर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. बस्सी रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एमएल गृह उद्योग पर एक दिन पहले सड़े-गले माल से अचार बनाने की हजारों किलो सामग्री पकड़ने के बाद गुरुवार को दूसरे दिन यहीं पर ही साँस की हजारों बोतलें सीज की गई। चिकित्सा विभाग की केन्द्रीय निदेशालय टीम की इस फैक्ट्री पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। फैक्ट्री में वेजिटेबल साँस बनाया जाता है, लेकिन मौके पर सब्जी की 100 ग्राम मात्रा भी नहीं मिली। टीम ने यहां साँस का निर्माण स्टार्च, रंग और पानी से किए जाने के अंदेशे पर 500 कर्टन में रखी करीब 6 हजार लीटर साँस की बोतलों को सीज कर दिया है।

राज्य नोडल अधिकारी सुनील सिंह ने बताया कि यहां मात्र 20-22 रुपए प्रति लीटर में खुदरा विक्रेताओं को साँस की आपूर्ति की जाती है। इस पर एमआरपी 47 रुपए अंकित है। इतनी कम लागत और उस पर भी करीब दोगुनी एमआरपी के साथ विक्रय किया जा रहा है। यहां अचार बनाने में काम आने वाला करीब 6500 किलो कच्चा माल और मिला है, जो कि खाने योग्य नहीं है। एक दिन पहले भी यहां ऐसा ही 23 हजार किलो माल मिला था। इन्हें मिलाकर अब कुल नहीं खाने योग्य माल 30, 500 किलो हो गया है।

जो स्टार्च मिला वह संचालक के खुद के ब्रांड का है। संचालक ने बताया कि वह स्टार्च भी बाजार में बेचता है। टीम ने तलाशी ली लेकिन सब्जियों के अवशेष भी नहीं मिले।

नष्ट कराने में लगा पूरा दिन



दर्जनों वाहनों में भरकर दिन भर नष्ट कराया माल: एक दिन पहले फैक्ट्री को आगे की कार्रवाई के लिए सीज किया गया था। दूसरे दिन कार्रवाई के बाद करीब 8500 किलो अचार और रेड चिली साँस को एक कमरे में रखवाकर सीज कर दिया गया है। यहां खराब माल को दर्जनों वाहनों में भरकर दिन भर नष्ट करवाया जाता रहा।

मलाई नहीं, यूरिया जा रहा शरीर में

यह दूध है या विष
बीते साल के नमूनों
की जांच का सच

जयपुर @ पत्रिका. जिस दूध को शरीर के लिए पोषक व अमृत मानकर हम पी रहे हैं, वह शत प्रतिशत शुद्ध है ही नहीं। चिकित्सा विभाग की ओर से पिछले साल प्रदेश भर से लिए गए जांच नमूनों में यह सच सामने आया है। प्रदेश भर में जाँचें गए 744 जांच नमूनों में से करीब 18 प्रतिशत यानि 137 नमूने ऐसे पाए गए जो तय मानकों के अनुरूप नहीं थे, जानलेवा थे, मिस ब्रांड थे या उनमें शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक तत्व पाए गए। इनमे से 10 नमूने तो यूरिया जैसी घातक मिलावट वाले भी पाए गए। विशेषज्ञों के अनुसार इस श्रेणी के नमूने इंसान के लिए जानलेवा भी हो सकते हैं। हालांकि विभाग की ओर से दूध के नमूनों में भी एक साल में एक भी मिलावटिये को सजा नहीं हो पाई है।

अपराध गम्भीर मगर
जुर्माना लगाकर छोड़ा

स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार जो नमूने पिछले साल सामने आए हैं, उनमें से सब स्टैंडर्ड (मानक) श्रेणी के 125, असुरक्षित (अनसेफ) श्रेणी के 10 और मिस ब्रांड श्रेणी के 2 नमूने पाए गए हैं। इनमे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार कानूनी कार्यवाही व जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

ऐसे नुकसान पहुंचाते हैं रसायन

फर्मीलिन

नकली दूध को लंबे समय तक सही हालत में रखने और गाढ़ा बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं

शरीर पर दुष्प्रभाव : आंखों की रोशनी धीरे-धीरे जा सकती है, आंतों में घाव हो जाते हैं, मस्कुलर सिस्टम ठप होता है।

यूरिया

थक्का बनाता है। दूध में इसलिए मिलाया जाता है, ताकि गर्म करने पर यूरिया मलाई की तरह दूध की सतह पर जम जाए

शरीर पर दुष्प्रभाव : इसका सेवन करने से इंसान मंदबुद्धि होता चला जाता है। मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं, लगातार सेवन से पुरुषों की पितृत्व शक्ति कम होने लगती है

हाइड्रोजन परॉक्साइड

यह रसायन तेजाब है और झाग बनाता है, असली की तरह झाग बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है

शरीर पर दुष्प्रभाव : शरीर में भोजन से किया कर फूड टॉक्सिन जहर बनाता है, इसके सेवन से व्यक्ति हमेशा थका-थका महसूस करता है और अनिद्रा का शिकार हो सकता है

कम गुणवत्ता वाला ग्लूकोज
दूध में इसका उपयोग स्वाद व गाढ़पन के लिए करते हैं। ताकि दूध में रसायनों की दुर्गंध और स्वाद छिप जाए।

शरीर पर दुष्प्रभाव : घटिया ग्लूकोज का सेवन करने और अत्यधिक मात्रा में लेने पर शरीर का सुत्र होना और लकवे की शिकायत हो सकती है।

इस तरह बनता है बेहतर और
अच्छी गुणवत्ता वाला साँस

साँस बनाने में किसी भी तरह का रंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

टोमेटो साँस बनाया जा रहा है तो सिर्फ पके हुए बढ़िया लाल टमाटर और अच्छी गुणवत्ता के मसाले ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं

कैचअप साँस में बिल्कुल भी

पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता

एक लीटर साँस में 100 एमएल से अधिक पानी नहीं होना चाहिए

वेजिटेबल साँस में 60 प्रतिशत टोमेटो, 40 प्रतिशत सब्जियां और 10 प्रतिशत पानी हो सकते हैं



हाईकोर्ट व सरकार से आश्वासन, 25 से काम पर लौटेंगे वकील



प्रदर्शन और जाम : कलक्ट्रेट से हाईकोर्ट तक गुरुवार को वाहन रैली निकालते अधिवक्ता और इस दौरान लगा लम्बा जाम।

फोटो : पत्रिका

शिक्षा का अधिकार हर साल फरवरी के द्वितीय सप्ताह में शुरू होती रही है प्रक्रिया

लाखों परिवारों को इंतजार, अब तक शुरू नहीं हुई प्रवेश प्रक्रिया



पत्रिका
न्यूज
पंच

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राज्य में लाखों परिवार अपने बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने आरटीई प्रवेश के लिए अब तक दिशा-निर्देश ही जारी नहीं किए हैं। हर वर्ष यह प्रक्रिया फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू होती

रही है लेकिन इस बार केवल 10 दिन बचने के बावजूद सरकार ने प्रवेश के लिए आवेदन लेना तो दूर, दिशा-निर्देश भी जारी नहीं किए हैं।

गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना जरूरी है। गरीब श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों व वंचित वर्ग में अजा-जजा श्रेणी के बच्चों को शामिल किया जाता है। राज्य में गरीब वर्ग का पैमाना सालाना एक लाख रुपए की आय है। राज्य सरकार स्कूलों को इन सीटों पर दिए गए प्रवेश का पुनर्भुगतान करती है।



मामला जानकारी में नहीं है। देर क्यों हो रही है, दिखवाता हूँ।

गोविंद सिंह डोटसरा,
शिक्षा राज्यमंत्री

हर साल यह रहता है आरटीई प्रवेश का टाइम फ्रेम

दिशा-निर्देश व विज्ञापन जारी करना : फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : मार्च के दूसरे सप्ताह तक

ऑनलाइन लॉटरी : मार्च का दूसरा सप्ताह

स्कूलों में रिपोर्टिंग : मार्च का तीसरा सप्ताह

बच्चों का स्कूल में प्रवेश : मार्च के दूसरे सप्ताह तक

- अनारक्षित सीटों के बाद

आरक्षित सीट पर फाइनल प्रवेश : जुलाई

अभिभावक परेशान

श्यामसुंदर शर्मा : हर साल फरवरी की शुरुआत में आवेदन शुरू हो जाते हैं। इस साल अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। मुझे बेटे के प्रवेश के लिए आवेदन करना है। रोजाना साइट चैक करता हूँ।

कैलाश वर्मा : आरटीई की विजप्ति अब तक जारी नहीं हुई है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया में देर होगी। सरकार को जल्दी विजप्ति जारी करनी चाहिए।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भर्ती में वकीलों का कोटा सुरक्षित रखने सहित विभिन्न मांगों पर वकीलों को हाईकोर्ट प्रशासन व राज्य सरकार से लिखित आश्वासन मिल गया है। इसके आधार पर गुरुवार रात को वकीलों ने 25 फरवरी से काम पर लौटने घोषणा की। इससे पहले वकीलों ने सुबह वाहन रैली निकाली और हाईकोर्ट पहुंचकर मुख्य भवन के बाहर प्रदर्शन किया।

राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन ने वकीलों की मांगों को कमेंटियों के सामने रखने का लिखित आश्वासन दिया है। वकीलों की संघर्ष समिति की बैठक में इस आश्वासन पर संतोष जाहिर किया गया और आंदोलन वापस लेने पर सहमति हो गई। इससे पहले अधिवक्ता संघर्ष समिति के संयोजक राजेश कर्नल के नेतृत्व में वकीलों ने सुबह जिला कलक्ट्रेट सर्कल से हाईकोर्ट तक वाहन रैली निकाली। रैली खासाकोटी, पांचबत्ती, स्टेच्यू सर्कल होते हुए हाईकोर्ट पहुंची।



एकजुटता दिखाते अधिवक्ता।

दफ्तर भी नहीं आए, अनुपस्थिति लगाई
तीन दिन से तहसीलदार लापता, न
ढूंढने के प्रयास और न कार्रवाई



एसीबी ने कहा,
नहीं आए तो नोटिस
देकर करेंगे तलब

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. कलक्ट्रेट स्थित तहसील परिसर में 3 दिन पहले हुई एसीबी की कार्रवाई के बाद एक ओर जहां कर्मचारियों में खलबली मची हुई है, वहीं जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव अनजान बने हुए हैं।

प्रकरण के बाद से लापता हुए तहसीलदार गजेन्द्र गोयल को जिला कलक्टर ने न तो तलाशने का प्रयास कराया, न कोई कार्रवाई की है। पिछले 3 दिन से तहसीलदार कारण बताए बिना ही अनुपस्थित चल रहे हैं। कलक्टर ने सिर्फ तहसीलदार का चार्ज दूसरे अधिकारी को सौंपकर इतिश्री कर ली है।

इधर एसीबी की कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों में अब तक खलबली मची हुई है। कलक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को भी सत्राटा ही पसरा नजर आया। न तो लोगों की ज्यादा आवाजाही दिखी, न ज्यादातर कर्मचारी सीट पर नजर आए। गौरतलब है कि एसीबी ने कमरा नंबर 56 से तहसीलदार के

फोन बन्द

इधर, राजस्थान पत्रिका ने तहसीलदार के नम्बर पर कॉल किया तो फोन बंद मिला।

तहसीलदार अनुपस्थित चल रहे हैं, उनका चार्ज दूसरे अधिकारी को दिया है। लगातार अनुपस्थित रहे तो विभागीय कार्रवाई करेंगे।

जगरूप सिंह यादव, जिला कलक्टर

रीडर विजय सिंह को रिश्तत लेते पकड़ा था। मुख्य भूमिका में माना जा रहा तहसीलदार का चालक अशोक अभी भी फरार है। एसीबी के एएसपी आलोक सिंघल ने बताया कि तहसीलदार को बुलाया लेकिन उनसे फिलहाल सम्पर्क नहीं हुआ है।

प्रकरण में आरोपियों के सामने बैठाकर तहसीलदार से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद ही कहा जा सकेगा कि प्रकरण में उनकी भूमिका रही है या नहीं। तहसीलदार नहीं आए तो नोटिस देकर बुलाया जाएगा। उधर, प्रशासन ने तहसीलदार गजेन्द्र गोयल का चार्ज सविता शर्मा को सौंपा है। गोयल 6 माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

रोडवेज

बकाया 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते
के भुगतान का आदेश जारी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर . राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया 6 प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं। निगम के मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार रोडवेज कर्मियों और पेंशनर्स को एक सितंबर 2018 से महंगाई भत्ता 142 से बढ़ाकर



148 प्रतिशत मिलेगा। इसका नकद भुगतान किया जाएगा। इससे रोडवेज पर 1.80 करोड़ का अतिरिक्त मासिक भार आएगा।